भारत संघ और अन्य

बनाम

यू. पी. स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 8860/2014)

16 सितंबर, 2014

[जे. चेलामेश्वर और ए. के. सिकरी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996- धारा 11, 14 और 15- अनुबंध की सामान्य शर्तें, 2001- धारा 64 (1) (ii) सरकारी निगम-यू. ओ. के और निजी पक्ष-प्रतिवादी बीच अनुबंध-मध्यस्थता खंड के संदर्भ में मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजे गए पक्षों के बीच विवाद समझौते के संदर्भ में गठित-मध्यस्थता की विफलता न्यायाधिकरण चार साल के लिए मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करेगा - उच्च न्यलालय द्वरा एकल की नियुक्ति के साथ वैकल्पिक मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थ-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः सामान्य नियम यह है कि एक स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति में की जानी चाहिए 'विकल्प के मामले में' डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया' लागू की जाएगी मध्यस्थ और न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कदम उठाएंगे। पक्षों के बीच सहमत प्रक्रिया को अलग रखते हुए अदालतें ऐसी स्थितियों को सुधारने के लिए शक्तिहीन नहीं हैं - कार्रवाई में उतरना और अपनी शक्तियों का प्रयोग करना धारा 11 में निहित एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करना, ताकि दूसरे पक्ष के हितों की समान रूप से रक्षा की जाती है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का पहला सिद्धांत "निष्पक्ष, त्वरित और सस्ता" है एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण।" दूसरा सिद्धांत है - प्रक्रिया के चयन में पार्टी की स्वायत्तता। इसका मतलब है कि यदि कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है मध्यस्थता समझौता जिस पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं, जिसका आम तौर पर सहारा लेना पड़ता है। यह इस कारण से है, एक सामान्य प्रथा के रूप में, न्यायालय इस बात पर जोर देगा कि पक्षकारों को उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जिसके लिए उनके पास है सहमत हुए। यह बनाते समय भी लागू होगा स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति और सामान्य नियम कि एक स्थानापन्न मध्यस्थ की ऐसी नियुक्ति है प्रावधानों के अनुसार भी किया जाना चाहिए नियुक्ति पर लागू मूल समझौते का प्रक्रिया के चयन में पार्टी की स्वायत्तता रही है उन मामलों से विचलित जहां एक पक्ष के अनुसार कार्य नहीं करके डिफ़ॉल्ट किया है निर्धारित प्रक्रिया। [पैरा 18] [1196-एफ-एच; 1197 - ए-डी]

1.2 सरकार निगमों/राज्य के बीच अनुबंधों के मामले में निजी के स्वामित्व वाली कंपनियाँ पार्टियाँ/ठेकेदार, समझौते की शर्तें आमतौर पर सरकारी कंपनी या क्षेत्र उपक्रम द्वारा तैयार की जाती हैं। सरकारी अनुबंध हैं मोटे तौर पर दो प्रकार के मध्यस्थता खंड, पहला जहां एक नामित अधिकारी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है; और दूसरा, जहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी एक प्रबंध निदेशक की तरह, एकमात्र के रूप में कार्य करने के लिए एक नामित अधिकारी को नामित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे खंड जो मध्यस्थ का गठन करने के लिए सरकार एक प्रमुख स्थिति है न्यायाधिकरण को वैध माना जाता है। साथ ही यह भी एक भारी और जिम्मेदार कर्तव्य डालता है ऐसे व्यक्तियों/अधिकारियों की नियुक्ति के लिए व्यक्ति पदनाम मध्यस्थ जो केवल कार्य करने में सक्षम नहीं हैं स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से, लेकिन एक स्थिति में हैं मध्यस्थता के संचालन में पर्याप्त समय दें। अगर सरकार ने उन अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नामित किया है जो मध्यस्थता के लिए

समय देने में सक्षम नहीं हैं कार्यवाही या के रूप में कार्य करने में असमर्थ होना। बार-बार स्थानांतरण आदि के कारण मध्यस्थ, फिर 'पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया' का सिद्धांत कम से कम उन मामलों में जहां स्वयं के लिए मध्यस्थ, के मामले में लागू किया जाना है मध्यस्थों को भी प्रतिस्थापित करें और न्यायालय हस्तक्षेप करेगा प्रक्रिया को अलग रखते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति करना। जिस पर दोनों पक्षों के बीच सहमति हो। हालांकि, यह होगा यह किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है कि क्या इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय इस संबंध में शक्तिहीन नहीं है। [पैरा 19] [1197-एफ-एच; 1198-ए-डी]

1.3 प्रत्यर्थी को उसकी दया पर छोड़ना अपीलार्थी इस प्रकार अपीलार्थी को शक्ति प्रदान करता है - एक अन्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करना पहले से लगी गंभीर चोट का अपमान करना मध्यस्थता के गैर निष्कर्ष के कारण प्रत्यर्थी कार्यवाही तब भी जब वर्ष 2007 में विवाद उठाया गया था। मामले में, पोषित और परोपकारी उद्देश्य और विवादों के त्वरित समाधान का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा किया जाना है, यह बन जाता है नियुक्त करने के लिए व्यक्ति पदनाम का बाध्य कर्तव्य ऐसे मध्यस्थ जिनके पास पर्याप्त समय हो। यह एक आम दृश्य है कि अधिकारी जो भयानक हैं अपने अन्य नियमित कार्यों में व्यस्त, उनके कारण स्थिति और पद को मध्यस्थ बनाया जाता है। उनके लिए, उनके अन्य कर्तव्यों का निर्वहन अधिक माना जाता है महत्व (और स्वाभाविक रूप से) और उनकी भूमिका के रूप में मध्यस्थ पीछे बैठ जाते हैं। इस तरह का व्यवहार मध्यस्थता मामलों में आकस्मिक दृष्टिकोण दिखाना है मध्यस्थता की उत्पत्ति के लिए अभिशाप। इसलिए, जहाँ सरकार अधिकार और शक्ति ग्रहण करती है स्वयं के लिए, एकतरफा मध्यस्थता खंड में, नियुक्त करने के लिए विवादों के मामले में मध्यस्थों को अधिक होना चाहिए। मध्यस्थों के चयन में सतर्क और अधिक जिम्मेदार जो मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करने की स्थिति में हैं

अपने अन्य कर्तव्यों के साथ समझौता किए बिना कुशल तरीके से। नियुक्ति का समय आ गया है। अधिकारियों को इस तरह के पहलुओं पर निर्णय लेने में विफल होना पड़ता है जो (तत्काल मामले में), न्यायालय शक्तिहीन नहीं हैं अधिनियम की धारा 11 में निहित अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसी स्थितियों का निवारण करना। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए अधिनियम, ताकि ब्याज दूसरी तरफ समान रूप से संरक्षित है। [पैरा 22] [1200 - सी-एच; 1201-ए-बी]

उत्तर पूर्वी रेलवे बनाम ट्रिपल इंजीनियरिंग वर्क्स 2014 (9) एस. सी. सी. 288; यशविथ कंस्ट्रक्शंस (पी) लिमिटेड बनाम सिम्प्लेक्स कंक्रीट पाइल्स इंडिया लिमिटेड और एक और 2006 (3) पूरक एससीआर 96: (2006) 6 एससीसी 204 - संदर्भित किया गया।

अर्थशास्त्र नीति विभाग और मास्को शहर का विकास बनाम बैंकर्स ट्रस्ट कं. (2004) ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 314-संदर्भित। मस्टिल और बॉयड द्वारा वाणिज्यिक मध्यस्थता, 2001; मध्यस्थता का कानून और व्यवहार और ओ. पी. मल्होत्रा द्वारा सुलह-संदर्भित।

केस लॉ रेफरेन्स

2014 (9) एससीसी 288, संदर्भित किया गया, पैरा 10, 15, 18, 22.

(2004) ई.डब्ल्यू.सी.ए.सिविल 314, संदर्भित किया गया, पैरा 16.

2006 (3) पूरक एससीआर 96, संदर्भित किया गया, पैरा 18

सिविल न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8860/2014

पटना उच्च न्यायालय का न्यायिक संदर्भ मामला सं. 3/2011 के निर्णय और आदेश की दिनांक 03-08-2011 से।

तुषार मेहता, एएसजी, मधुरिमा मृदुल, सुश्री हनी कुमारी, एस. एन. तेरदल, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

विवेक सिंह, लक्ष्मी रमन सिंह, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय ए. के. सिकरी, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. पक्षों के वकील को विस्तार से सुना गया है यह अपील। उठाये गए विवाद को निर्धारित करने के लिए भारत संघ द्वारा दायर इस अपील में, चुनौती दी गई है उच्च न्यायालय का दिनांकित 03.08.2011 निर्णय, न्यूनतम तथ्य जिनका उल्लेख करने की आवश्यकता है, वे निम्नलिखित हैंः

अपीलार्थी ने एक समझौता किया था उत्तरदाता गाइड बांधों के निर्माण के लिए कौन सा अनुबंध, नदी पर रेल पुल की नींव और उप-संरचना पटना के दीघा घाट के पास गंगा नदी और उक्त समझौते में विभिन्न नियम और शर्तें थीं। का खंड 64 (1) (ii) अनुबंध 2001 की सामान्य शर्त (संक्षेप में 'जी. सी. सी.') में एक मध्यस्थता खंड शामिल है जो इसके लिए प्रदान किया गया है मध्यस्थता के माध्यम से पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेना उक्त के संदर्भ में गठित किए जाने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा समझौता।

3. संबंधित पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए कथित अनुबंध और प्रत्यर्थी के अनुरोध पर जिसमें सभी सदस्य रेलवे अधिकारी थे। यह खेद का विषय है कि चार वर्ष की समाप्ति के बावजूद उक्त न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा नहीं किया और मामला रखा गया स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/स्थगन आदि के कारण लटकना।

4. उत्तरदाता ने इसके कारण नाराज़गी महसूस की मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मामले का विस्तार और चुना गया केस नं. 10/2010 दाखिल करने के लिए

अनुरोध करें। दाखिल करने के समय भी उस मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में एक रिक्ति थी। जब इस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा 09.03.2011 पर लिया गया था, उस समय, अपीलार्थी ने उक्त रिक्ति को भर दिया था। लेना। उक्त याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था अदालत ने 09.03.2011 दिनांकित आदेश के माध्यम से अंतिम मौका दिया मध्यस्थता न्यायाधिकरण के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश के साथ तीन महीने की अवधि पटना में प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से आदेश दिया। यह दिनांकित 09.03.2011 आदेश में भी कहा गया था। कि यदि मध्यस्थता कार्यवाही के भीतर पूरा नहीं किया जाता है न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में, प्रत्यर्थी को फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता होगी और न्यायालय विवश होगा मध्यस्थता के अनुसार उचित आदेश पारित करना और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)।

5. मध्यस्थ न्यायाधिकरण को उक्त के बारे में अवगत कराया गया था आदेश के रूप में इसकी प्रति 25.03.2011 को उसके सामने पेश की गई थी इसका मतलब है कि इसे पूरा करना था 25.06.2011 द्वारा मामला, हालाँकि, उक्त आबंटित के भीतर भी समय, कार्यवाही को समाप्त नहीं किया गया था और इसलिए, प्रत्यर्थी ने अनुरोध मामला सं. 3/2011 दिनांक 29.06.2011 को दायर किया।

6. अपीलार्थी ने उपरोक्त याचिका का विरोध किया विभिन्न आधारों पर प्रत्यर्थी और अपने स्वयं के कारण भी दिए जिनके कारण मध्यस्थ न्यायाधिकरण पूरा नहीं करेगा कार्यवाही। यह भी बताया गया कि हालांकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षकारों के मामले को सुनने और निर्णय लेने के लिए तैयार था यह अंत में 22.07.2011 पर, प्रतिवादी ने सूचित किया था उक्त याचिका दाखिल करने का न्यायाधिकरण जिसके कारण न्यायाधिकरण द्वारा मामले का स्थगन।

7. उच्च न्यायालय ने विभिन्न तिथियों पर ध्यान दिया न्यायाधिकरण द्वारा 25.03.2011 के बीच तय की गई सुनवाई और 25.06.2011 और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देरी हुई मध्यस्थता कार्यवाही जानबूझकर की गई थी। इतना ही नहीं, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य अपनी देरी जारी रख रहे थे 2007 से उसके समक्ष मामले को तय करने की रणनीति और चार इस प्रक्रिया में कई साल बीत चुके थे। न्यायाधिकरण भी लड़खड़ा गया था मामले को समाप्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश देने के बाद तीन महीने और लंबे स्थगन दिए गए उच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करना। पदनाम न्यायाधिकरण के सदस्यों का यह रवैया लापरवाही के रूप में किसी भी कानून के लिए कोई पवित्रता के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति उनकी भूमिका उच्च न्यायालय के आदेशों पर, उच्च न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी यहाँ प्रत्यर्थी का और के अधिदेश को अलग रखें न्यायालय द्वारा एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के साथ न्यायाधिकरण स्वयं।

8. तत्काल अपील में, चुनौती दी जाती है उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय इस याचिका के साथ कि यह उच्च न्यायालय के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए खुला नहीं था क्योंकि यह अपने स्वयं के मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने का अधिकार नहीं था और वह भी मध्यस्थता खंड के विपरीत। श्री तुषार मेहता, विद्वान ए. एस. जी याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए ने एक इस ओर से जोरदार निवेदन है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय में निहित। उनका निवेदन था कि अधिनियम की योजना के अनुसार भले ही के अधिदेश मध्यस्थ न्यायाधिकरण को समाप्त किया जाना था, नया न्यायाधिकरण हो सकता है इसका गठन केवल मध्यस्थता समझौते के अनुसार किया गया था। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय अधिक से अधिक, अपीलार्थी को एक अन्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया जी. सी. सी. के खंड 64 के अनुसार।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील, उच्च न्यायालय के निर्णय को जोरदार याचिका के साथ उचित ठहराने का एक प्रभावी प्रयास किया कि जब इसका उद्देश्य ही न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा मध्यस्थता को हतोत्साहित किया जाता है जो, कार्यवाही को खींच रहे थे, अदालत शक्तिहीन नहीं थी जी. सी. सी. के खंड 64 के ढांचे से परे यात्रा करना और एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करें। उन्होंने उल्लेख किया विवादित मामले में उच्च न्यायालय के विशिष्ट निष्कर्षों के लिए इस संबंध में निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अवलोकन करते हुएः

> "10. उल्लिखित सभी तथ्य और परिस्थितियाँ ऊपर दर्शाया गया है कि मध्यस्थता में हुई देरी कार्यवाही जानबूझकर की गई थी। न्यायाधिकरण ने निर्णय लेने में अपनी विलंबकारी रणनीति जारी रखी 2007 से मध्यस्थता कार्यवाही और जब लगभग इस न्यायालय द्वारा चार साल के विशिष्ट निर्देश दिए गए थे। अनुरोध मामले में 09.03.2011 दिनांकित आदेश पारित किया गया के सं.10/2011 उक्त अधिकारियों ने एक के लिए संकोच नहीं किया इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देश की अवज्ञा करने का क्षण और याचिकाकर्ता के बावजूद अपने विलंबकारी रवैये को जारी रखा 25.03.2011 पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपनी दलीलें दायर कीं और 21.04.2011 से जवाब दें। इसके बाद, लंबा स्थगन का उल्लंघन करते हुए मध्यस्थता कार्यवाही में प्रदान किया गया था नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देश पटना में और मध्यस्थ द्वारा निर्धारित लंबी तारीख के बाद भी न्यायाधिकरण, कभी-कभी प्रतिवादी-अधिकारियों को लंबा समय लगा अपना जवाबी जवाब दाखिल करने के लिए स्थगन और अधिकांश माध्यस्थम न्यायाधिकरण का एक या

दूसरा सदस्य उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने यह देखा कि तीन का समय इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश द्वारा दिए गए महीने 09.03.2011 समाप्त हो गया है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का यह रवैया स्पष्ट रूप से विशिष्ट निर्देशों की अवज्ञा के बराबर है इस न्यायालय का दिनांकित 09.03.2011 आदेश पारित किया गया अनुरोध मामला सं.10/2010

11. ये सभी तथ्य एक बहुत ही दुखद स्थिति का भी खुलासा करते हैं। मामले कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्य अयोग्य हैं & किसी भी मानक से अप्रभावी, पूरी तरह से लापरवाही अपने कर्तव्यों के प्रति और किसी भी कानून के लिए कोई पवित्रता नहीं है या उच्च न्यायालय के आदेशों के लिए, जो इस पर निर्भर हैं उन्हें। उन्हें दिए जाने वाले सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि में स्पष्ट रूप से सरकारी खजाने की बर्बादी साबित हुई, जो यह लोगों की मेहनत की कमाई से आता है। रेलवे को इन टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए और इस न्यायालय का आदेश और तदनुसार कार्य करना।

12. जहाँ तक इस मामले का संबंध है, यह पहले से ही था इसके द्वारा पारित दिनांक 09.03.2011 आदेश में उल्लिखित के अनुरोध मामले सं.10/2010 में न्यायालय ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट करता है तीन महीने के भीतर मध्यस्थता पूरी नहीं हुई थी उक्त आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तिथि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष, याचिकाकर्ता होगा इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता और यदि द्वारा दावा किए गए तथ्य याचिकाकर्ता को सही पाया गया, यह न्यायालय होगा उचित आदेश पारित करने के लिए

विवश अधिनियम के साथ। उक्त परिस्थितियों में और याचिकाकर्ता का दावा साबित पाया गया है न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण के संबंध में, इस अनुरोध मामले की अनुमति है और प्रतिवादी द्वारा नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण अधिकारियों को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है और एक एकमात्र मध्यस्थ होता है मध्यस्थता कार्यवाही तय करने के लिए नियुक्त किया गया बिना कोई अनुचित स्थगन दिए शीघ्रता से कोई भी पक्ष।"

10. उन्होंने आगे कहा कि उत्तर के मामले में पूर्वी रेलवे बनाम ट्रिपल इंजीनियरिंग वर्क्स, तय किया गया सिविल अपील सं.6275/2014 में 13.08.2014 पर (से उत्पन्न) एस. एल. पी (ग) सं.20427/2013), लगभग समान रूप में परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने इसी तरह के निर्देशों को मंजूरी दी थी पटना उच्च न्यायालय।

11. यह विवाद में नहीं है कि जीसीसी के खंड 64 के अनुसार, निर्धारित तरीके से तीन मध्यस्थ नियुक्त किए जाने हैं। उसमें पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में। प्रासंगिक खंड 64 का वह भाग जिससे हम संबंधित हैं - वर्तमान स्थितियों को नीचे निकाला गया हैः

"64.(1)(i) मध्यस्थता की मांग-किसी भी स्थिति में पक्षकारों के बीच विवाद या मतभेद इस अनुबंध का निर्माण या संचालन, या संबंधित किसी भी मामले में पक्षों के अधिकार और देनदारियाँ किसी भी कारण से या के रूप में प्रश्न, विवाद या मतभेद रेलवे द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को रोक देना, जिसके लिए ठेकेदार हकदार होने का दावा कर सकता है, या यदि रेलवे 120 दिनों के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तब और किसी भी समय में ऐसे मामले में, लेकिन किसी

भी अपेक्षित मामले को छोड़कर इन शर्तों के खंड 63 में निर्दिष्ट, ठेकेदार, 120 दिनों के बाद लेकिन उनकी प्रस्तुति के 180 दिनों के भीतर विवादित मामलों पर अंतिम दावा, लिखित रूप में मांग करेगा विवाद या मतभेद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाए।

XX XX XX

64.(3)(क)(1) ऐसे मामलों में जहां सभी दावों का कुल मूल्य एक साथ जोड़े गए प्रश्न में 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) से अधिक नहीं है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में शामिल हैंः एकमात्र मध्यस्थ जो या तो महाप्रबंधक होगा जे. ए. श्रेणी से नीचे के रेलवे के राजपत्र अधिकारी का उस ओर से महाप्रबंधक द्वारा नामित ग्रेड। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति 60 दिनों के भीतर की जाएगी। जिस दिन मध्यस्थता के लिए लिखित और वैध मांग की जाती है रेलवे द्वारा प्राप्त किया जाता है।

64. (3) (क) (ii) खंड 64 (3) द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों में जे. ए. से कम नहीं तीन राजपत्रित रेलवे अधिकारी श्रेणी, मध्यस्थों के रूप में। इसके लिए रेलवे राजपत्रित के 3 से अधिक नामों का एक पैनल भेजेगा एक या अधिक विभागों के रेलवे अधिकारी ठेकेदार को रेलवे, जिसे सुझाव देने के लिए कहा जाएगा महाप्रबंधक के लिए पैनल से अधिकतम 2 नाम ठेकेदार द्वारा नामित व्यक्ति के रूप में नियुक्ति। द जनरल प्रबंधक उनमें से कम से कम एक को नियुक्त करेगा - ठेकेदार का नामांकित व्यक्ति और वसीयत भी, एक साथ पैनल से या पैनल के बाहर से मध्यस्थों की शेष संख्या नियुक्त करें, जो विधिवत

रूप से इंगित करता है विभाग को समान दर्जा माना जाएगा रेलवे के अन्य विभागों के एसए ग्रेड के अधिकारी मध्यस्थों की नियुक्ति के उद्देश्य से।

64. (3) (क) (iii) यदि एक या अधिक मध्यस्थ ऊपर के रूप में नियुक्त मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से इनकार करता है, मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यालय से हट जाता है, या खाली हो जाता है उसका/उनका कार्यालय/कार्यालय या असमर्थ या अनिच्छुक है/हैं किसी भी कारण से मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यों का पालन करना जो भी हो या मर जाए या जनरल की राय में प्रबंधक अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है, जनरल प्रबंधक नए मध्यस्थ/मध्यस्थों की नियुक्ति करेगा उसके स्थान पर उसी तरीके से कार्य करें जिसमें पूर्ववर्ती मध्यस्थ/मध्यस्थ नियुक्त किए गए थे। ऐसा पुनर्गठित न्यायाधिकरण अपने विवेकाधिकार पर, उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ें जिस पर यह था पिछले मध्यस्थों द्वारा छोड़ दिया गया।

12. इस स्तर पर, हम योजना पर ध्यान दे सकते हैं साथ ही, उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए। प्रासंगिक प्रावधान तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला गयाः

"14. कार्य करने में विफलता या असंभवता। - (1) जनादेश एक मध्यस्थ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा यदि

(क) वह वैधानिक रूप से या वास्तविक रूप से प्रदर्शन करने में असमर्थ हो जाता है। उसके कार्य या अन्य कारणों से अनुचित कार्य करने में विफल रहता है देरी; और

(ख) वह अपने पद से हट जाता है या पक्षकार इस पर सहमत हो जाते हैं - उनके कार्यकाल की समाप्ति।

(2) यदि किसी विवाद के बारे में कोई विवाद बना रहता है उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट आधार पार्टी तब तक आवेदन कर सकती है जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो। अधिदेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय को।

(3) यदि, इस धारा या धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत, एक मध्यस्थ अपने कार्यालय से हट जाता है या एक पक्ष सहमत हो जाता है एक मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति के लिए, यह संदर्भित किसी भी आधार की वैधता की स्वीकृति का संकेत नहीं देगा। इस धारा में या धारा 12 की उप-धारा (3) में।

15. अधिदेश की समाप्ति और प्रतिस्थापन मध्यस्थ। - (1) उल्लिखित परिस्थितियों के अलावा धारा 13 या धारा 14 में, एक मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त होगा -

(क) जहाँ वह किसी कारण से पद से हट जाता है; या

(ख) पक्षकारों के समझौते द्वारा या उसके अनुसार।

(2) जहाँ मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाता है, प्रतिस्थापन मध्यस्थ के अनुसार नियुक्त किया जाएगा नियुक्ति पर लागू होने वाले नियम मध्यस्थ को बदला जा रहा है।

(3) जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, जहां एक मध्यस्थ को उप-धारा (2), किसी भी सुनवाई के तहत प्रतिस्थापित किया जाता है मध्यस्थ न्यायाधिकरण।

(4) जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, एक आदेश या प्रतिस्थापन से पहले मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय इस धारा के तहत मध्यस्थ का निर्णय अमान्य नहीं होगा। केवल इसलिए कि इसमें बदलाव आया है मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना।

32. कार्यवाही की समाप्ति। - (1) मध्यस्थ कार्यवाही को अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। या उप-धारा के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा

(2) मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए एक आदेश जारी करेगा मध्यस्थता कार्यवाहियों की समाप्ति जहां -

(क) दावेदार अपना दावा वापस ले लेता है, जब तक कि - प्राप्त करने में अपनी ओर से एक वैध हित को पहचानता है विवाद का अंतिम समाधान,

(ख) पार्टियों की समाप्ति पर सहमत हैं कार्यवाही, या

(ग) मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया कि निरंतरता किसि कारन से व्यर्थ या असम्भव हो गयी हो।

(3) धारा 33 और धारा की उप-धारा (4) के अधीन रहते हुए 34, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिदेश समाप्त हो जाएगा मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति के साथ।"

13. जैसा कि धारा 14 के पढ़ने से स्पष्ट है, जब मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक पक्ष के लिए खुला है अधिदेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय। अनुभाग 15 कुछ और आकस्मिकताएँ प्रदान करता है जब एक का अधिदेश मध्यस्थ को बर्खास्त किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय एक स्पष्ट निष्कर्ष पर आया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने कार्य को करने में विफल रहा, और ठीक ही है। यह एक स्पष्ट मामला है न्यायाधिकरण के सदस्यों की ओर से मामले में आगे बढ़ने में असमर्थता क्योंकि मामला लगभग चार साल तक चला, बिना किसी तुकबंदी या उचित कारणों के। सदस्यों ने नहीं किया जब उन्हें तीन महीने का समय देकर एक और जीवन दिया गया, तब भी वे अपने तरीके सुधारते हैं। वस्तुतः एक पूर्व-खाली आदेश पारित किया गया था उच्च न्यायालय द्वारा, लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण अप्रभावित रहा और उच्च न्यायालय के निर्देशों को बेपरवाह तरीके से लिया। इसलिए, आदेश को समाप्त करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण का कार्य त्रुटिहीन है। विवादित का यह पहलू के समय अपीलार्थी द्वारा आदेश पर सवाल भी नहीं उठाया जाता है वर्तमान अपील की सुनवाई।

14. तथापि, अपीलार्थी का तर्क यह है कि यदि ऐसा था तो अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिस्थापन मध्यस्थों को नियुक्त किया जाना चाहिए था "उन नियमों के लिए जो नियुक्ति पर लागू होते थे मध्यस्थ को बदला जा रहा है।" इस आधार पर, यह प्रस्तुतिकरण था श्री मेहता का, विद्वान ए. एस. जी., कि उच्च न्यायालय को होना चाहिए था जी. सी. सी. के खंड 64 में निहित प्रावधान का सहारा लिया।

15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर यही स्थिति होगी। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है भारत के सभी संघों में उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई को अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। धारा 11 के तहत एक आवेदन से

निपटने के दौरान मामले अधिनियम या जोड़ों में खेलने के लिए एक जगह है और उच्च न्यायालय को कुछ के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाता है परिस्थितियाँ? यदि हाँ, तो वे परिस्थितियाँ क्या हैं? यह है। यह वही पहलू है जिस पर इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचार किया गया था ट्रिपल इंजीनियरिंग वर्क्स (ऊपर) में। विभिन्न का ध्यान रखना निर्णयों, न्यायालय ने इंगित किया कि यह धारणा कि उच्च न्यायालय अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए बाध्य था। हाल ही में पार्टियों के बीच एक महत्वपूर्ण क्षरण देखा गया है अतीत। उक्त निर्णय के पैरा 5 में, वे निर्णय जहां उपरोक्त "शास्त्रीय धारणा" का विचलन किया गया है ध्यान में रखा जाता है। इसलिए, यह प्रजनन के लिए उपयोगी होगा। पैरा 6 और 7 के साथ उक्त पैरा नीचे दिया गया हैः

> "5. "शास्त्रीय धारणा" कि उच्च न्यायालय मध्यस्थता की धारा 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद संक्षिप्त में 'अधिनियम') बीच के अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करनी चाहिए पार्टियों ने ऐस पाइपलाइन में एक महत्वपूर्ण क्षरण देखा कॉन्ट्रैक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, (2007) 5 एस. सी. सी. 304 जिसमें इस न्यायालय ने लिया था। यह विचार कि हालांकि पक्षों के बीच अनुबंध होना चाहिए असाधारण रूप से उनसे विचलन का पालन किया जाए परिस्थितियाँ स्वीकार्य होंगी। प्रेम महत्वपूर्ण है। विकास एक निर्णय में आया था जो जल्द ही आया इसके बाद भारत संघ बनाम। भारत बैटरी विनिर्माण कंपनी (पी) लिमिटेड, (2007) 7 एस. सी. सी. 684 जिसमें पुंज लॉयड में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद लिमिटेड वी. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड, (2006) 2 एससीसी 638

यह था अभिनिर्धारित किया कि एक बार पीड़ित पक्ष आवेदन दायर करता है अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय को, अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ। द. निहितार्थ कि न्यायालय इससे विचलन करने के लिए स्वतंत्र होगा अनुबंध की शर्तें स्पष्ट हैं। जाहिर है कि एस पाइपलाइन (सुप्रा) और भारत बैटरी में द्विभाजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (पी) लिमिटेड (ऊपर) उत्तर रेलवे प्रशासन, मंत्रालय रेलवे, नई दिल्ली बनाम। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, (2008) 10 एस. सी. सी. 240 जहाँ उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अदालत की मांग की गई थी "से" अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जोर दिया गया उप-अनुभाग में दिखाई देने वाला आवश्यक उपाय करें। (6) धारा 11 और आगे यह निर्धारित करते हुए कि उक्त अभिव्यक्ति को आवश्यकता के साथ पढ़ा जाना चाहिए अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (8)। यह पद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, (2009) 8 में आगे स्पष्ट किया गया था & अधिनियम की धारा 11 का सारांश उद्धृत किया जा सकता है। इसमें उप-अनुच्छेद (vi) और (vii) को पुनः प्रस्तुत करके नीचेः

"(vi) मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित सदस्य, जबकि धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करना नियुक्ति को प्रभावी बनाने का प्रयास करेगा मध्यस्थता खंड में विहित प्रक्रिया।

(vii) यदि परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तो न्यायसंगत स्थिति पैदा हो रही है की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में संदेह नामित व्यक्ति, या यदि अन्य परिस्थितियाँ आवश्यक हैं अनदेखी करके एक स्वतंत्र

मध्यस्थ की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अनदेखा कर सकता है नामित मध्यस्थ और किसी और को नियुक्त करें।

6. उपरोक्त चर्चा इसके बिना पूरी नहीं होगी में व्यक्त इस न्यायालय के दृष्टिकोण का संदर्भ भारतसंघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट, (2009) 4 एससीसी 523 जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति इसके विपरीत है। निर्दिष्ट नियुक्ति की आवश्यकता वाले समझौते के लिए अधिकारियों को इस आधार पर वैध माना गया था कि मध्यस्थता कार्यवाही एक से अधिक के लिए समाप्त नहीं हुई थी प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हुए दशक। सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (ऊपर) की रिपोर्ट का अनुच्छेद 25 इस न्यायालय ने सुझाव दिया था कि सरकार, वैधानिक प्राधिकरणों और सरकारी कंपनियों को करना चाहिए मध्यस्थता खंडों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार करें सेवारत अधिकारियों की नियुक्ति और प्रोत्साहन मध्यस्थता में व्यावसायिकता।

7. एक घोषणा डीप ट्रेडिंग कंपनी बनाम भारतीय तेल निगमन और अन्य (2013) 4 एससीसी 35 पुंज लॉयड लिमिटेड (उपर्युक्त) में निर्धारित कानूनी स्थिति का पालन किया। जिसने बदले में दो न्यायाधीशों की पीठ का अनुसरण किया था दातार स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम टाटा फाइनेंस लिमिटेड, (2000) 8 एस. सी. सी. 151 में निर्णय ज़ब्त करने का सिद्धांत अपनी नियुक्ति करने के लिए समझौते के तहत एक पक्ष के अधिकार धारा 11 (6) के तहत कार्यवाही एक बार मध्यस्थ अधिनियम और भी अधिक औपचारिक

रूप से शुरू हो गया था डीप ट्रेडिंग कंपनी (ऊपर) विषय में अंतर्निहित, बेशक, धारा 11 (8) के प्रावधानों के लिए, जो किसी भी स्थिति में प्रावधान उत्तरी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। रेलवे प्रशासन (ऊपर) अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन केवल एक ही रखने की आवश्यकता को मूर्त रूप देना अधिकारिता के प्रयोग के समय को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 11 (6)।"

16. मध्यस्थता कार्यवाही का तेजी से समापन शायद ही हो जोर देने की आवश्यकता है। यह ध्यान देने योग्य होगा कि कि इंग्लैंड में भी उसी वर्ष अनसिर्टल मॉडल कानून की तर्ज पर आधुनिक मध्यस्थता कानून लागू किया गया था। भारतीय कानून जिसे अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के रूप में जाना जाता है और यह 31 जनवरी, 1997 से प्रभावी हो गया। इसका इलाज किया जाता है। अंग्रेजी मध्यस्थता के सबसे व्यापक वैधानिक सुधार के रूप में कानून। इस अधिनियम की संरचना पर टिप्पणी करते हुए, और बॉयड ने अपने "वाणिज्यिक मध्यस्थता, 2001 सहयोगी खंड" में लिखा दूसरे संस्करण में, टिप्पणी की है कि इस अधिनियम की स्थापना की गई थी चार स्तंभों पर। इन स्तंभों का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

(क) पहला स्तंभः तीन सामान्य सिद्धांत।

(ख) दुसरा स्तम्ब : न्यय्दिकरन का सामान्य कर्तव्य

(ग) तीसरा स्तंभः दलों का सामान्य कर्तव्य।

(घ) चौथा स्तंभः अनिवार्य और अर्ध अनिवार्य प्रावधान।

जहाँ तक पहले स्तंभ का संबंध है, इसमें तीन सिधअथ समलित जिस पर इस अधिनियम् संरचित हैं। इन सिद्धांतों का उल्लेख एक अंग्रेजी न्यायालय द्वारा किया गया है के अर्थशास्त्र नीति और विकास विभाग मास्को शहर बनाम बैंकरों ट्रस्ट कं., (2004)

ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 314। उस मामले में, मैन्स, एल. जे. इस अधिनियम के उद्देश्य को संक्षेप में निम्नलिखित में प्रस्तुत किया गया हैः शब्दः 'संसद ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में निर्धारित किया है कि एक सुधार और अधिक स्वतंत्र को प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान करना, साथ ही निजी और गोपनीय, सहमति की प्रणाली न्यायालय की केवल सीमित संभावनाओं के साथ विवाद समाधान जहां जनता के हित में आवश्यक हो वहां भागीदारी और बुनियादी निष्पक्षता '। अधिनियम की धारा 1 में तीनों का उल्लेख किया गया है। मध्यस्थता कानून के मुख्य सिद्धांत। - (1) तेज़, सस्ता और एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष सुनवाई; (ii) पक्ष की स्वायत्तता; और ((iii) न्यूनतम अदालती हस्तक्षेप। यह प्रावधान होना चाहिए उद्देश्यपूर्ण रूप से लागू किया। किसी के अर्थ के बारे में संदेह के मामले में इस अधिनियम के प्रावधानों को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

17. "ओ. पी. मल्होत्रा ऑन द लॉ एंड प्रैक्टिस" पुस्तक में मध्यस्थता और सुलह (सुश्री इंदु मल्होत्रा द्वारा संशोधित तीसरा संस्करण), यह सही पाया गया है कि भारतीय मध्यस्थता अधिनियम यह भी उपरोक्त चार मूलभूत स्तंभों पर आधारित है।

18. पहले स्तंभ का पहला और सर्वोपरि सिद्धांत है "निष्पक्ष, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा त्वरित और सस्ती सुनवाई" मध्यस्थता का। दिलचस्प बात यह है कि दूसरा सिद्धांत जो है अधिनियम में मान्यता प्राप्त चयन में पार्टी की स्वायत्तता है प्रक्रिया। इसका मतलब है कि यदि कोई विशेष प्रक्रिया है मध्यस्थता समझौते में निर्धारित जो पक्षों के पास है सहमत हैं, जिसका आम तौर पर सहारा लेना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर। यह नियुक्ति करते समय भी लागू होगा स्थानापन्न मध्यस्थ और सामान्य नियम यह है कि स्थानापन्न मध्यस्थ की ऐसी नियुक्ति भी की जानी चाहिए। मूल समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर लागू स्टेज। (यशविथ कंस्ट्रक्शंस (पी) लिमिटेड बनाम सिम्प्लेक्स् कंक्रीट पाइल्स इंडिया

लिमिटेड और दूसरा, (2006) 6 एस. सी. सी. 204 हालाँकि, चुनाव में पार्टी की स्वायत्तता का यह सिद्धांत प्रक्रिया को उन मामलों से अलग किया गया है जहां एक पक्षकारों ने कार्य न करके चूक की है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। ऐसे कई ऐसे उदाहरण जहाँ यह कार्रवाई की जाती है और न्यायालय व्यक्ति पदनाम विफल होने पर मध्यस्थ की नियुक्ति करें कार्य करने के लिए, ट्रिपल इंजीनियरिंग (ऊपर) के पैरा 5 में ध्यान दिया जाता है काम करता है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ये थे वे मामले जहाँ स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है धारा 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा किया गया 'पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया' का लेखा। हम हैं, वर्तमान मामले में, वैकल्पिक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित जहाँ पहले का मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्रदर्शन करने में विफल रहा है। हालांकि, पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया के उपरोक्त सिद्धांत को इसके द्वारा बढ़ाया जाता है ऐसे मामलों में न्यायालय के साथ-साथ निर्णय से स्पष्ट है सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (ऊपर)।

19. सरकार के बीच अनुबंधों के मामले में निगम/निजी दलों के साथ राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियाँ/ठेकेदार, समझौते की शर्तें आमतौर पर द्वारा खींची जाती हैं सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सरकारी अनुबंधों में मोटे तौर पर दो प्रकार के मध्यस्थता होते हैं। खंड, जहाँ पहले एक नामित अधिकारी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है; और दूसरा, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी एक प्रबंध निदेशक की तरह, एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक नामित अधिकारी को नामित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे खंड जो सरकार को प्रभावी बनाते हैं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की स्थिति को वैध माना जाता है। साथ ही, यह एक भारी और जिम्मेदार 3 भी डालता है ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने का व्यक्ति पदनाम पर कर्तव्य/ अधिकारी मध्यस्थ के रूप में जो न केवल कार्य करने में सक्षम हैं स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से, लेकिन समर्पित करने की स्थिति में हैं

मध्यस्थता के संचालन में पर्याप्त समय। अगर सरकार उन अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नामित किया है जो सक्षम नहीं हैं मध्यस्थता कार्यवाही के लिए समय देना या बनना बार-बार स्थानांतरण के कारण मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ आदि, तो 'डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया' का सिद्धांत कम से कम में ऐसे मामले जहां सरकार ने नियुक्ति की भूमिका ग्रहण की है स्वयं मध्यस्थों के लिए, विकल्प के मामले में लागू किया जाना है मध्यस्थ भी और न्यायालय नियुक्त करने के लिए कदम उठाएगा मध्यस्थ उस प्रक्रिया को अलग रखते हुए जिस पर सहमति हो दलों के बीच। हालाँकि, यह तथ्यों पर निर्भर करेगा एक विशेष मामला कि क्या इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए लिया जाए या नहीं। हम जिस बात पर जोर देते हैं वह यह है कि न्यायालय नहीं है इस संबंध में शक्तिहीन।

20. सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (ऊपर) में कहाँ एक दशक से अधिक समय से मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित थी इस न्यायालय द्वारा एक प्रक्रिया का उपहास पाया गया। यह पीड़ा न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में निम्नलिखित तरीका व्यक्त किया गया हैः

> "15. वैकल्पिक विवाद समाधान का उद्देश्य मध्यस्थता की प्रक्रिया त्वरित और प्रभावी होनी चाहिए। एक निजी मंच के माध्यम से विवादों का निपटान दलों की पसंद। यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण में सेवारत शामिल हैं विवाद के पक्षों में से एक के अधिकारी, सदस्यों के रूप में मध्यस्थता समझौते और ऐसे न्यायाधिकरण के संदर्भ में कार्रवाई के कारण गैर-कार्यात्मक बना दिया जाता है या ऐसी पार्टी की निष्क्रियता या देरी, या तो बार-बार स्थानांतरण द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के ऐसे सदस्यों का या ऐसा करने में विफल रहने पर मध्यस्थों को बदलने के लिए तेजी से कदम उठाएँ मध्यस्थता समझौते की शर्तें, मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित, धारा के तहत

शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक 11 अधिनियम के तहत, कदम उठा सकते हैं और उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

16. हम यह समझने में विफल हैं कि महाप्रबंधक क्यों रेलवे ने बार-बार पैनल प्रस्तुत किए जिनमें शामिल थे उन अधिकारियों के नाम जिनका निकट भविष्य में स्थानांतरण होना था। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एक सेवारत अधिकारी सेवा की वश्यकताओं के कारण स्थानांतरित किया जाता है और नियोक्ता की स्थानांतरण नीति और वह केवल इसलिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन अधिकारियों के बने रहने की संभावना है एक विशेष स्थान पर अकेले मध्यस्थों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और यह कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण जिसमें सेवारत अधिकारी शामिल हैं, मामले का शीघ्रता से निर्णय लें।

17. सेवारत अधिकारियों के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरणों का गठन अलग-अलग दूर-दराज के स्थानों से बचना चाहिए। वहाँ कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है, लेकिन एक होना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण है तुरंत गठित किया जाता है और मध्यस्थता आगे नहीं बढ़ती है वर्षों और दशकों।

18. जैसा कि ऊपर देखा गया है, मामला अब लंबित है। उस तारीख से लगभग दस साल तक जब मध्यस्थता की मांग पहली बार की गई थी और लगभग कोई प्रगति नहीं हुई थी। समय के बीतने को ध्यान में रखते हुए, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को खंड 64 के

संदर्भ में पुनर्गठित किया जाना है, अन्य न्यायाधिकरण के सदस्य दो को भी बदलने की आवश्यकता हो सकती है।

19. मध्यस्थ न्यायाधिकरण में देरी और लगातार परिवर्तन मध्यस्थता की प्रक्रिया का मजाक बनाते हैं। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, हम विचार है कि दिल्ली के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति एकमात्र मध्यस्थ के रूप में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है अनुच्छेद 136 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए भारत का संविधान।"

21. न्यायालय द्वारा स्वयं मध्यस्थ की नियुक्ति सीई, मध्यस्थता खंड से हटकर, इसलिए नहीं हैहोना और कानून की सर्वोच्च अदालत रिपोर्ट का एक स्वीकार्य प्रस्ताव बन गया है जिसे एक कानूनी सिद्धांत कहा जा सकता है जो आया है इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा स्थापित किया जाएगा। कारण। इस तरह की कार्रवाई पर बहस करना दूर की बात नहीं है और ऊपर पहले से ही ध्यान दिया गया है।

22. वर्तमान मामले में, ट्रिप्पल इंजीनियरिंग वर्क्स (सुप्रा) और सिंह के समान बिल्डर्स सिंडिकेट (सुप्रा) पर हम लगभग तथ्य स्थिति पाते हैं, यदि अपीलार्थी का तर्क अनुमति दी जाती है, यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों की गलती के लिए अपीलार्थी को प्रीमियम देने के बराबर होगा जो थे अपीलार्थी द्वारा नियुक्त किए जाने के अलावा किसी और द्वारा नियुक्त नहीं। जैसा कि बताया गया है। ऊपर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल नहीं उठाया है न्यायालय जहाँ तक उसने पूर्व के अधिदेश को समाप्त कर दिया है कार्य पूरा करने में असमर्थता के कारण मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपीलार्थी की दया पर इस प्रकार शक्ति प्रदान करते हुए एक अन्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए अपीलार्थी राशि प्रदान करेगा।

मध्यस्थता का निष्कर्ष न निकलने के कारण प्रतिवादी को पहले से ही हुई गंभीर चोट का अपमान करना। मध्यस्थता द्वारा विवादों के त्वरित समाधान का उद्देश्य कार्यवाही पूरी की जानी है, यह सीमा बन जाती है ऐसे मध्यस्थ (ओं) को नियुक्त करने के लिए नामित व्यक्ति का कर्तव्य जो इस कार्य में भाग लेने के लिए उनके पास पर्याप्त समय है तेजी से। यह एक आम दृश्य है कि अधिकारी जो अपने अन्य नियमित कार्यों में बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि उनकी स्थिति और स्थिति को मध्यस्थ बनाया जाता है। उनके लिए, उनके अन्य कर्तव्यों का निर्वहन अधिक महत्वपूर्ण है (और स्वाभाविक रूप से) और मध्यस्थों के रूप में उनकी भूमिका पीछे रह जाती है। इस तरह का व्यवहार मध्यस्थता में आकस्मिक दृष्टिकोण दिखाता है मामले मध्यस्थता की उत्पत्ति के लिए अभिशाप हैं। अतः, जहाँ सरकार अधिकार और शक्ति ग्रहण करती है - विवादों के मामले में, इसे अधिक सतर्क और अधिक होना चाहिए उन मध्यस्थों को चुनने के लिए जिम्मेदार जो भारत संघ की स्थिति में हैं। एक कुशल तरीके से मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करने के लिए, अपने अन्य कर्तव्यों के साथ समझौता किए बिना। समय आ गया है। जब नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को ऐसे पहलुओं पर निर्णय लेना होता है जो विफल हो जाते हैं (जैसा कि तत्काल मामले में होता है), तो अदालतें ऐसा नहीं करती हैं। कार्रवाई में आकर ऐसी स्थितियों को सुधारने के लिए शक्तिहीन और धारा 11 में निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए अधिनियम, ताकि दूसरे का हित पक्ष समान रूप से संरक्षित है।

23. उपरोक्त को देखते हुए, हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं। वर्तमान अपील जो लागत के साथ खारिज की जाती है।

निधि जैन याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।